GEO IAS
It's about quality

26 June 2024

GEO Daily

Daily Current Affairs

GEO IAS

SOURCES

THE HINDU | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | PIB | AIR | live mint | THE FINANCIAL EXPRESS | ET ECONOMIC TIMES.COM

Date: 26 June 2024

Important News Articles

1. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने eSakhsya ऐप का परीक्षण किया - द हिंदू
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को नई सुविधाओं के साथ नया रूप दिया जाएगा - द हिंदू
3. रेलवे वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों की गति कम करेगा- द हिंदू
4. भविष्य के युद्धों की लागत बहुत अधिक है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए: CDS
5. चीन का चांग'ए-6 यान चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा - द हिंदू

Editorials, Gists and Explainers

6. जम्मू-कश्मीर का शत्रु एजेंट अध्यादेश क्या है?
7. महाराष्ट्र के जल संकट का विश्लेषण - द हिंदू
8. भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता - इंडियन एक्सप्रेस
9. लैंसेट अध्ययन: आधे भारतीय शारीरिक रूप से अस्वस्थ - इंडियन एक्सप्रेस
10. भारत में मुस्लिम जनसंख्या एक्सप्लोशन का मिथक- इंडियन एक्सप्रेस

Quick Look

1. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
2. SBM-U 2.0
3. भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (FIEO)
4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)
5. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS)

महत्वपूर्ण समाचार लेख

सामान्य अध्ययन II

1. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने eSakhsya ऐप का परीक्षण किया - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे

- BNS, 2023
- NCRB

समाचार:

- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ई-साक्ष्य (e-evidence/ eSakhsya) का परीक्षण कर रहा है, जो एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन है, जो पुलिस को आपराधिक मामले में अपराध के दृश्यों को रिकॉर्ड करने, तलाशी और जब्ती करने तथा फाइल को क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने में मदद करेगा।

मुख्य बिंदु:

- प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस अधिकारी को एक सेल्फी अपलोड करनी होगी।
- राज्य पुलिस विभागों के साथ साझा किए गए विवरण के अनुसार, प्रत्येक रिकॉर्डिंग अधिकतम चार मिनट लम्बी हो सकती है और प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के लिए ऐसी कई फाइलें अपलोड की जा सकती हैं।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) जो भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लेगी; भारतीय साक्ष्य (BS) जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेगी; तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 का स्थान लेगी, ये सभी जुलाई से लागू होने वाली हैं।

दोषसिद्धि दर

- BNSS प्रत्येक आपराधिक मामले में तलाशी और जब्ती की अनिवार्य दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग तथा उन सभी मामलों में अनिवार्य फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाता है, जहां अपराध के लिए सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है।
- हार्डवेयर और क्लाउड स्पेस खरीदना एक महंगा मामला है और कई राज्यों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे जांच में एकरूपता लाने में भी मदद मिलेगी, जिससे दोषसिद्धि दर में वृद्धि होगी।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन उन सभी पुलिस स्टेशनों के लिए उपलब्ध होगी जो इसे पंजीकृत और डाउनलोड करेंगे।
- एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ऐप का परीक्षण अंतिम चरण में है और पुलिस को दो विकल्प दिए गए हैं।
- यदि कनेक्टिविटी की समस्या है, तो पुलिस अपने निजी मोबाइल फोन जैसे डिवाइस पर अपराध स्थल को रिकॉर्ड कर सकती है और हैश वैल्यू जनरेट कर सकती है, पुलिस स्टेशन वापस आकर फाइल अपलोड कर सकती है।
- दूसरा तरीका यह है कि वे सीधे eSakhsya के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं जिसके लिए अच्छी इंटरनेट स्पीड की आवश्यकता होती है।
- एक अन्य पुलिस अधिकारी ने आगाह किया कि साक्ष्य प्रस्तुत करने की श्रृंखला की पवित्रता का पालन करना होगा, अन्यथा इससे आरोपी को फायदा हो सकता है।
- कई आरोपी प्रक्रियागत खामियों के कारण कानून के चंगुल से बच निकलते हैं।
- नए कानून में सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है, अगर डिजिटल साक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी सी भी समस्या आती है, तो अपराधी छूट सकते हैं।
- फोरेंसिक साक्ष्य को हमेशा गुणवत्ता के आधार पर चुनौती नहीं दी जाती, बल्कि आदेश श्रृंखला के आधार पर चुनौती दी जाती है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को नई सुविधाओं के साथ नया रूप दिया जाएगा - द हिंदू

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

प्रीलिम्स टेकअवे
- PMAY
- पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता

समाचार:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को नई सुविधाओं के साथ नया रूप दिया जाएगा

मुख्य अंश:
- PMAY (शहरी) को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
- मिशन का उद्देश्य झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों सहित गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करना है, ताकि सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर मिल सके।
- इस पुनर्गठन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना के लिए पंजीकरण कराने वाले लाभार्थियों तक पहुंचने में कोई देरी न हो।
- मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 और वर्ष 2022-23 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता और राज्यों को प्रोत्साहित करके शहरों में बुनियादी शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और गति लाने के लिए एक योजना की भी घोषणा की थी।
- दोनों योजनाओं ने अन्य बातों के अलावा राज्यों को अनुकूल उप-नियमों और राज्यों द्वारा सक्षम नीति अपनाने के माध्यम से 66 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र के लिए किफायती आवास के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
- इस योजना के अंतर्गत, राज्यों ने बताया है कि उनकी किफायती आवास नीति के अंतर्गत सक्षम प्रावधानों के माध्यम से, पिछले चार से पांच वर्षों में लगभग 5,00,000 आवास इकाइयों का निर्माण किया गया है।
- इसके अलावा, शहरी नियोजन सुधारों के तहत, स्थानीय झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को भी प्रोत्साहित किया गया है।

सामान्य अध्ययन III

3. रेलवे वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस ट्रेनों की गति कम करेगा- द हिंदू

प्रासंगिकता: इन्फ्रास्ट्रक्चर: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, हवाई अड्डे, रेलवे आदि।

प्रीलिम्स टेकअवे
- गतिमान एक्सप्रेस
- वंदे भारत एक्सप्रेस

समाचार:
- भारतीय रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही चुनिंदा मार्गों पर वंदे भारत और गतिमान एक्सप्रेस सहित प्रीमियम ट्रेनों की अधिकतम गति को वर्तमान 160 किमी प्रति घंटे से घटाकर 130 किमी प्रति घंटे कर देगा।

मुख्य बिंदु
- प्रस्ताव के अनुसार, जो 'सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वांछित' है, गतिमान और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की गति 160 किमी प्रति घंटे से घटाकर 130 किमी प्रति घंटे की जाएगी, जबकि शताब्दी एक्सप्रेस की गति 150 किमी प्रति घंटे से घटाकर 130 किमी प्रति घंटे की जाएगी।
- सूत्रों ने बताया कि इससे इन मार्गों पर चलने वाली कम से कम 10 सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में 25-30 मिनट की वृद्धि होगी और इनके समय में भी बदलाव होगा।

TPWS विफलता
- TPWS को समाप्त करने या ट्रेनों की गति को 130 किमी प्रति घंटे तक कम करने का उत्तर रेलवे का प्रस्ताव 6 नवंबर, 2023 से बोर्ड के पास लंबित था।
- मंडल रेल प्रबंधक की रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि TPWS की मरम्मत या रखरखाव संभव नहीं था, इसलिए रेलवे बोर्ड से प्रीमियम ट्रेनों को डाउनग्रेड करने का अनुरोध किया गया ताकि इन्हें "130 किमी प्रति घंटे की अधिक सुरक्षित गति" पर संचालित किया जा सके।

4. भविष्य के युद्धों की लागत बहुत अधिक है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए: CDS

प्रीलिम्स टेकअवे
- CDS
- WASP

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

समाचार:
- भविष्य के युद्धों की लागत "बहुत अधिक" होने की बात कहते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने संसाधनों और जनशक्ति को अनुकूलतम बनाने तथा भविष्य के हथियारों और प्रणालियों को वहन करने के लिए दक्षता लाने की आवश्यकता पर बल दिया।
- नागरिक और सैन्य संसाधनों के बीच एकीकरण की बातचीत से पहले, सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच एकीकरण होना चाहिए।

मुख्य बिंदु:
- लगभग 170 ऐसी पहल जहां तीनों सेनाएं एकीकृत तरीके से एक साथ काम कर सकती हैं।
- CDS ने वायु सेना के वारफेयर एंड एयरोस्पेस स्ट्रैटेजी प्रोग्राम (WASP) कोर्स के सेमिनार में कहा, "सेनाएं समय, संसाधन, प्रक्रिया, बुनियादी ढांचे और जनशक्ति का अनुकूलन करने में सक्षम होंगी।"

सामरिक कार्यक्रम
- WASP 15 सप्ताह का एक रणनीतिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसे वर्ष 2022 में प्रतिभागियों को भूराजनीति, भव्य रणनीति और व्यापक राष्ट्रीय शक्ति की गहरी समझ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- इसका संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के साथ मिलकर किया जाता है।
- तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण के लिए तार्किक कदम यह होगा कि इस दृष्टिकोण को अन्य सेनाओं तक भी ले जाया जाए।
- उदाहरण के लिए, नौसेना और तटरक्षक बल मिलकर सूची और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल का काम कर सकते हैं।
- हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भी आवश्यक रसद और बुनियादी ढांचे में शामिल कर सकते हैं।

वैकल्पिक तरीके
- निम्नलिखित महत्वपूर्ण तरीके –
  - सरकार को लागत कम करने में सहायता करें।
  - क्योंकि भविष्य के युद्धों की लागत बहुत अधिक होगी, इसलिए हथियार प्रणालियां और प्लेटफॉर्म बहुत महंगे होंगे।
  - हमें काम करने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचना होगा। यह बहुत व्यावहारिक और समयबद्ध होना चाहिए।
- विद्वान योद्धा एक सैन्य पेशेवर होता है जो आज के जटिल और गतिशील सुरक्षा वातावरण में बौद्धिक कुशाग्रता को युद्ध कौशल के साथ जोड़ता है।
- भारत की सामरिक संस्कृति की चर्चा करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह ऐतिहासिक अनुभवों और निरंतर विकसित होते भू-राजनीतिक परिवेश से आकार लेती है।
- इसमें रणनीतिक स्वायत्तता, सावधानी और क्षेत्रीय अखंडता पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है।

5. चीन का चांग'ए-6 यान चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा - द हिंदू

प्रीलिम्स टेकअवे
- आर्टेमिस एकॉर्ड
- मून मिशन

प्रासंगिकता: आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टेक्नोलॉजी, जैव-टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में जागरूकता।

समाचार:
- चीन का चांग'ए-6 यान चंद्रमा के कम खोजे गए दूरवर्ती भाग से चट्टान और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा है, जो विश्व में पहली बार हुआ है।

मुख्य बिंदु:
- चीनी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लौटाए गए नमूनों में 2.5 मिलियन वर्ष पुरानी ज्वालामुखी चट्टानें और अन्य सामग्री शामिल होगी

- वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इससे चंद्रमा के दोनों ओर भौगोलिक अंतर से जुड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
- निकट वाला भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, और दूर वाला भाग बाहरी अंतरिक्ष की ओर है। दूर वाले भाग में पहाड़ और प्रभाव क्रेटर भी पाए जाते हैं, जो चंद्रमा के निकट वाले भाग पर दिखाई देने वाले अपेक्षाकृत सपाट विस्तार के विपरीत है।

हाई होप्स

- यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव-ऐटकेन बेसिन में उतरा था।
  - यह एक प्रभाव गड्ढा है जो 4 अरब वर्ष से भी अधिक पहले निर्मित हुआ था।
- वैज्ञानिकों को जिन नमूनों की उम्मीद है, वे संभवतः बेसिन की विभिन्न परतों से आएंगे, जिनमें विभिन्न भूवैज्ञानिक घटनाओं के निशान होंगे।
- जबकि पिछले अमेरिकी और सोवियत मिशनों ने चंद्रमा के निकटवर्ती भाग से नमूने एकत्र किए थे, चीनी मिशन पहला था जिसने चंद्रमा के दूरवर्ती भाग से नमूने एकत्र किए थे।

एडिटोरियल, जिस्ट, एक्सप्लेनेर

6. जम्मू-कश्मीर का शत्रु एजेंट अध्यादेश क्या है?

प्रासंगिकता: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

प्रसंग:

- जम्मू-कश्मीर के DGP ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता करने वालों पर शत्रु एजेंट अध्यादेश, 2005 के तहत जांच एजेंसियों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- यह कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) से अधिक कठोर है और इसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है।
  - जिन लड़ाकों को जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता, उन्हें गोली मार दी जाती है।
  - जो लोग उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ दुश्मन एजेंट जैसा व्यवहार किया जाएगा।

शत्रु एजेंट अध्यादेश क्या है?

- जम्मू-कश्मीर शत्रु एजेंट अध्यादेश पहली बार वर्ष 1917 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन डोगरा महाराजा द्वारा जारी किया गया था। इसे 'अध्यादेश' इसलिए कहा जाता है क्योंकि डोगरा शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को अध्यादेश कहा जाता था।
- अध्यादेश के अनुसार,
  - "जो कोई भी दुश्मन का एजेंट है या दुश्मन की सहायता करने के इरादे से काम करता है,
  - या भारतीय सेनाओं के सैन्य या हवाई अभियानों में बाधा डालता है या जीवन को खतरे में डालता है, तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और साथ ही उसे जुर्माना भी देना होगा।
- वर्ष 1947 में विभाजन के बाद, इस अध्यादेश को तत्कालीन राज्य में कानून के रूप में शामिल किया गया तथा इसमें संशोधन भी किया गया।
- वर्ष 2019 में जब संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, तो जम्मू-कश्मीर के कानूनी ढांचे में भी कई बदलाव हुए।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें राज्य के कानूनों को सूचीबद्ध किया गया, जो जारी रहेंगे, जबकि कई अन्य को निरस्त कर दिया गया और उनके स्थान पर भारतीय कानून लागू किये गये।
- जबकि शत्रु एजेंट अध्यादेश और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम जैसे सुरक्षा कानून बने रहे;
  - रणबीर दंड संहिता को भारतीय दंड संहिता से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
  - वन अधिनियम, 2006 और SC ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सहित अन्य कानूनों को जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया गया।

अध्यादेश के तहत मुकदमे कैसे चलाए जाते हैं?

- शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुकदमा एक विशेष न्यायाधीश द्वारा चलाया जाता है, जिसे "सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से" नियुक्त किया जाता है।
- अध्यादेश के तहत, अभियुक्त अपने बचाव के लिए तब तक वकील नहीं रख सकता जब तक कि अदालत की अनुमति न हो।
- फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, और विशेष न्यायाधीश के फैसले की समीक्षा केवल "सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से चुने गए व्यक्ति द्वारा की जा सकती है और उस व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा"।
- ऐसे अनेक कश्मीरी हैं जिन पर शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुकदमा चलाया गया है या उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है।

7. महाराष्ट्र के जल संकट का विश्लेषण - द हिंदू

प्रासंगिकता: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन।

प्रसंग:

- पिछले वर्ष कमजोर मानसून के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कई हिस्सों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया था।
- यह स्थिति राज्य के तटीय क्षेत्रों से बिल्कुल विपरीत है, जहां अक्सर अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण भयंकर बाढ़ आती है।

वर्षा-छाया प्रभाव

- मराठवाड़ा पश्चिमी घाट के वर्षा-छाया क्षेत्र में स्थित है।
- जब अरब सागर से आने वाली नम हवाएँ इन पहाड़ों से टकराती हैं, तो वे ऊपर उठती हैं और ठंडी हो जाती हैं, जिससे पश्चिमी हिस्से में भारी वर्षा (2,000-4,000 मिमी) होती है।
- लेकिन जब तक ये हवाएँ घाटों को पार करके पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में उतरती हैं, तब तक वे अपनी अधिकांश नमी खो देती हैं, जिससे मराठवाड़ा बहुत अधिक शुष्क (600-800 मिमी) हो जाता है।
- IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा 2016 में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन मध्य महाराष्ट्र में स्थिति को और खराब कर रहा है।
- हाल ही में इस क्षेत्र में सूखे की गंभीरता और आवृत्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।
- परिणामस्वरूप, मराठवाड़ा और उत्तरी कर्नाटक राजस्थान के बाद भारत में दूसरे सबसे शुष्क क्षेत्र के रूप में उभरे हैं।

मराठवाड़ा क्षेत्र में गन्ने की फसल	सुझावात्मक उपाय

• मराठवाड़ा की कृषि पद्धतियाँ कम वर्षा के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
• इस क्षेत्र के जल संकट में एक प्रमुख योगदानकर्ता गन्ना खेती है।
• गन्ने को अपने बढ़ते मौसम में 1,500-2,500 मिमी पानी की आवश्यकता होती है, इसे लगभग हर दिन सिंचाई की भी आवश्यकता होती है।
• वर्ष 1950 और वर्ष 2000 के दशक के बीच गन्ने की खेती का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता रहा, लेकिन पिछले दशक में यह स्थिर हो गया।
• आज, यह फसल क्षेत्र के कुल फसल क्षेत्र का 4% है और सिंचाई के पानी का 61% खपत करती है।
• परिणामस्वरूप, ऊपरी भीमा बेसिन में नदी का औसत बहाव लगभग आधा हो गया है।
• गन्ने के मूल्य निर्धारण और बिक्री के लिए लंबे समय से चल रहे सरकारी समर्थन ने गन्ने की सिंचाई का विस्तार किया है, तथा अधिक पौष्टिक फसलों की सिंचाई को सीमित कर दिया है।
• दिसंबर 2023 से सरकार गन्ने के रस पर आधारित इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दे रही है , जो पानी की कमी वाले इस क्षेत्र के लिए शायद समझदारी नहीं है
  ○ महाराष्ट्र में उगाई जाने वाली 82% चीनी कम वर्षा वाले क्षेत्रों से आती है।
• मराठवाड़ा में मुख्य रूप से चिकनी काली मिट्टी है, जिसे स्थानीय रूप से "रेगुर" कहा जाता है।
• यह उपजाऊ है और नमी को अच्छी तरह से बनाए रखता है। हालांकि, इसमें घुसपैठ की दर कम है: जब बारिश होती है, तो पानी या तो जमा हो जाता है या बह जाता है, लेकिन भूजल को रिचार्ज करने के लिए नीचे नहीं जाता है।
• यहां तक कि मराठवाड़ा में भी जल की कमी एक समान नहीं है।
  ○ ऐसा इसलिए है क्योंकि भूजल धीरे-धीरे ऊंचे क्षेत्रों से घाटियों की ओर बढ़ता है।
  ○ ऊंचे इलाकों में स्थित कुएं मानसून के कुछ महीनों बाद सूख जाते हैं और यहीं पर पानी की कमी सबसे अधिक होती है।
	• पारंपरिक जलग्रहण प्रबंधन कार्य (जैसे जल संरक्षण संरचनाएं जैसे समोच्च खाइयां, मिट्टी के बांध, गली प्लग आदि का निर्माण)।
	• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निधियों का उपयोग गाद-फँसाने की व्यवस्था तैयार करने और समय-समय पर गाद निकालने के बारे में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जा सकता है।
	• कम वर्षा वाले क्षेत्र में, पानी की मांग के प्रबंधन में जल-कुशल सिंचाई का अभ्यास करना, सूखा-प्रतिरोधी फसलों की खेती करना और आजीविका में विविधता लाना शामिल है।
	• मराठवाड़ा को अन्य उच्च-मूल्य, कम पानी का उपयोग करने वाली फसलों की ओर भी बढ़ना चाहिए, जबकि गन्ना उत्पादन को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित करना चाहिए।

8. भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपदा प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: आपदा एवं आपदा प्रबंधन।

प्रसंग:

- पिछले महीने, लगातार बढ़ते तापमान के बीच, दिल्ली में बिजली की मांग ने बार-बार रिकॉर्ड तोड़ दिया।
- मध्य और पूर्वी भारत में कई स्थानों पर ऐसी ही या इससे भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा।

संबंधित डेटा

- यद्यपि पूर्व चेतावनी और त्वरित प्रतिक्रिया से आपदाओं में मानवीय हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है, फिर भी चरम मौसम की घटनाओं और आपदाओं से होने वाली आर्थिक और अन्य नुकसान बढ़ रहे हैं।
- इसका मुख्य कारण ऐसी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि है।
- सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2018 से वर्ष 2023 के बीच पांच वर्षों में राज्यों ने आपदाओं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने पर कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।
- उदाहरण के लिए, आजीविका की हानि या कृषि भूमि की उर्वरता में कमी के कारण दीर्घकालिक लागतें बहुत बड़ी हैं तथा समय के साथ इनके और भी बदतर होने का अनुमान है।
- विश्व बैंक की वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि गर्मी से संबंधित तनाव के कारण उत्पादकता में गिरावट से वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 34 मिलियन नौकरियां खत्म हो सकती हैं।
- आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं के कारण परिवहन, दूरसंचार और बिजली आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचना को होने वाली क्षति को अक्सर सरकारी आंकड़ों में नहीं गिना जाता है, खासकर तब जब ये सेवाएं निजी स्वामित्व वाली हों।

संधारणीय शामिल करना

- लगभग सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में अब इन घटनाओं से निपटने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया हेतु आपदा प्रबंधन योजनाएं मौजूद हैं।
- उदाहरण के लिए, आपदा-प्रवण क्षेत्रों में स्थित अस्पताल स्वयं को बैकअप विद्युत आपूर्ति से सुसज्जित कर रहे हैं, हवाई अड्डे और रेलवे जलभराव से बचने या उसे शीघ्र निकालने के लिए कदम उठा रहे हैं, तथा दूरसंचार लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है।
- लेकिन इस मोर्चे पर प्रगति धीमी रही है और भारत का बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है।
- किसी भी भारतीय राज्य में अपनी तरह के पहले अभ्यास में, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) ने ओडिशा में बिजली पारेषण और वितरण बुनियादी ढांचे का अध्ययन किया, जो चक्रवातों से उच्च जोखिम वाला राज्य है।
    - रिपोर्ट में पाया गया कि राज्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर अत्यंत कमजोर है।
- भारत अभी भी अपने बुनियादी ढांचे के विकास की प्रक्रिया में है। 2030 तक भारत में जितने बुनियादी ढांचे का निर्माण प्रस्तावित है, उनमें से अधिकांश का निर्माण अभी भी होना है।

CDRI

- आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), वर्ष 2019 में भारत की पहल पर स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
    - इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संधारणीय बनाना है।
- भारत में मुख्यालय वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, CDRI को इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित होना है।
- अब 30 से अधिक देश इस गठबंधन का हिस्सा हैं और अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए CDRI के साथ काम कर रहे हैं।
- लेकिन भारत में अब तक केवल कुछ ही राज्यों ने CDRI की विशेषज्ञता और सहयोग मांगा है।

आगे की राह

- निर्माण के समय ही आपदा प्रतिरोधक क्षमता को शामिल करना, बाद में इन सुविधाओं को पुनः जोड़ने की तुलना में अधिक आसान और लागत प्रभावी है।
- सभी आगामी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को जलवायु के प्रति स्मार्ट होना चाहिए, न केवल टिकाऊ और ऊर्जा कुशल, बल्कि आपदाओं के प्रति संधारणीय भी होना चाहिए।
- संपूर्ण विश्व की सेवा के लिए CDRI बनाने की पहल करने के बाद, भारत को सबसे अधिक संधारणीय बुनियादी ढांचे के लिए सही टेम्पलेट बनाने की आवश्यकता है, जो बहु-खतरनाक आपदाओं का सामना कर सके।

9. लैंसेट अध्ययन: आधे भारतीय शारीरिक रूप से अस्वस्थ - इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

समाचार:

- लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित नए आंकड़ों के अनुसार, आधी वयस्क भारतीय आबादी पर्याप्त शारीरिक गतिविधि के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करती है।

मुख्य बिंदु:

- सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारतीय वयस्कों में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि की व्यापकता वर्ष 2000 में 22.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 49.4 प्रतिशत हो गई है।
    - पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं।
- इसका अर्थ यह है कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वर्ष 2030 तक हमारी 60 प्रतिशत आबादी अस्वस्थ हो जाएगी तथा पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न करने के कारण बीमारियों के खतरे में रहेगी।

WHO की सिफारिशें • विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी वयस्कों के लिए प्रति सप्ताह कम से कम 150 से 300 मिनट की मध्यम एरोबिक गतिविधि की सिफारिश करता है। • अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि को प्रति सप्ताह 150 मिनट तक मध्यम-तीव्रता वाली गतिविधि, 75 मिनट तक तीव्र-तीव्रता वाली गतिविधि, या इनके समतुल्य संयोजन को न करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। • विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, शारीरिक निष्क्रियता से वयस्कों में हृदय संबंधी बीमारियों जैसे दिल के दौरे और स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह, मनोभ्रंश और स्तन तथा बृहदान्त्र के कैंसर का खतरा अधिक होता है। **अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष** • अनुमान बताते हैं कि 195 देशों में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के मामले में भारत 12वें स्थान पर है। • विश्व भर में, लगभग एक तिहाई वयस्क वर्ष 2022 में शारीरिक गतिविधि के अनुशंसित स्तर को पूरा नहीं कर पाएंगे। • उच्च आय वाले एशिया-प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण एशिया में शारीरिक निष्क्रियता की उच्चतम दर देखी गई • शारीरिक निष्क्रियता विश्व स्तर पर कई कारकों के कारण बढ़ रही है, जिनमें कार्य पैटर्न में परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन, सक्रिय परिवहन को और अधि	**भारत में शारीरिक निष्क्रियता** • भारत में यह स्थिति पत्रक विशेष रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि यहां के लोगों में अन्य लोगों की तुलना में हृदय रोग और मधुमेह जैसी गैर-संचारी बीमारियों के विकसित होने की संभावना कम से कम एक दशक पहले ही अधिक होती है। • भारत में किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि जनसंख्या स्तर पर शारीरिक गतिविधि का स्तर कम है, विशेष रूप से महिलाओं में, जो गलत तरीके से मानती हैं कि घरेलू काम करना शारीरिक व्यायाम का एक अच्छा रूप है। • निष्क्रियता सबसे अधिक मध्यम आयु वर्ग की शहरी महिलाओं में देखी जाती है, हालांकि यह सभी आयु और लैंगिक समूहों में कुछ हद तक देखी जाती है। • भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में महिलाओं में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि चिंता का विषय है, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में 14-20 प्रतिशत अंक पीछे हैं। **सुझावात्मक उपाय** • यद्यपि फिट इंडिया और लेट्स मूव इंडिया जैसे कार्यक्रम हाल के वर्षों में शुरू किए गए हैं, फिर भी हमें स्कूल, कार्यस्थल और सामुदायिक स्तर पर सेटिंग-आधारित समूह गतिविधि प्रोत्साहन प्रयासों की आवश्यकता है। • सुरक्षित साइकिल लेन, सुरक्षित पैदल पथ, हरित सामुदायिक स्थान और कम वायु प्रदूषण से सुरक्षित और आनंददायक आउटडोर गतिविधि संभव होगी

10. भारत में मुस्लिम जनसंख्या एक्सप्लोशन का मिथक- इंडियन एक्सप्रेस

प्रासंगिकता: महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके समाधान।

प्रसंग:

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज पर रोक लगा दी और बॉम्बे उच्च न्यायालय को अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।

भारत में मुस्लिम जनसंख्या एक्सप्लोशन का मिथक

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा किए गए नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वर्ष 2019-20 (NFHS-5) से पता चलता है कि
    - कई राज्य पहले ही प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, और भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) में लगातार गिरावट आ रही है।

- NHFS-5 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में वर्ष 2021 तक TFR प्रति महिला 2.0 बच्चे है, जो कि प्रति महिला 2.1 बच्चों के प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से थोड़ा कम है।

- आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2018-19 और नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) के वर्ष 2017 के आंकड़ों में भी भारत की जनसंख्या वृद्धि में कमी के बारे में इसी प्रकार के निष्कर्ष सामने आए थे।
- भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर हिंदू जनसंख्या से अधिक थी।
- इस एकल व्याख्या के इर्द-गिर्द उठे विवाद ने इस तथ्य को अस्पष्ट कर दिया कि वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के बीच दोनों विकास दरों के बीच का अंतर काफी कम हो गया था
- वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के आंकड़ों का उपयोग करके दोनों समुदायों के बीच प्रजनन अंतर की तुलना करने पर, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रजनन क्षमता में समानता स्पष्ट हो जाती है।
  - इसमें यह चेतावनी भी दी गई है कि चूंकि विभिन्न राज्य और समूह इस परिवर्तन के विभिन्न बिंदुओं पर हैं,
  - इस अभिसरण की प्रक्रिया में क्षेत्रों के बीच भिन्नताएं हैं यह तथ्य पहले के अध्ययनों से प्रमाणित है।
- प्रजनन क्षमता में गिरावट और जनसंख्या वृद्धि में गिरावट की दर को ध्यान में रखते हुए एक अन्य हालिया विश्लेषण में पाया गया कि पिछले दो दशकों में हिंदू प्रजनन क्षमता में गिरावट मुस्लिम प्रजनन क्षमता में गिरावट से पांच प्रतिशत कम थी।
  - जहाँ मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में हिंदुओं की तुलना में तेज़ गति से गिरावट आई है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2030 तक हिंदू-मुस्लिम प्रजनन दर में "पूर्ण अभिसरण" हो सकता है।
- NFHS के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में सभी धार्मिक समुदायों की प्रजनन दर में गिरावट आई है।
- विशेष रूप से मुसलमानों के परिवार के आकार में तेजी से कमी स्पष्ट है, क्योंकि मुसलमानों की प्रजनन दर वर्ष 1992-93 में 4.4 से लगभग आधी घटकर वर्ष 2020-21 में 2.4 हो गई है।
- पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने पाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक-आर्थिक विकास प्रजनन दर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य बिहार की तुलना में कम TFR दिखाते हैं
  - जिनकी इन संसाधनों तक पहुँच कम थी। इस प्रकार, प्रजनन दर के स्तर को प्रभावित करने वाला कारक धर्म नहीं था, बल्कि बेहतर सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विकास था।

गलत सूचना को चुनौती देना

- NFHS 5 के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि माता की शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रजनन दर उतनी ही कम होगी।
- सभी धार्मिक समूहों में मुसलमान आर्थिक रूप से सबसे अधिक वंचित हैं, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर भी खराब है - जो उच्च शिक्षा में उनके कम नामांकन स्तर से स्पष्ट है।
- वर्ष 2006 में सच्चर समिति की रिपोर्ट में मुसलमानों के बीच ऐसी सामाजिक-आर्थिक असमानता पर जोर दिया गया था।
- इस प्रकार, जनसंख्या वृद्धि पर बहस को शिक्षा, आर्थिक विकास, आजीविका, भोजन, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और लैंगिक न्याय में निवेश पर केंद्रित होना चाहिए।
- इसके अलावा, महिलाओं, विशेष रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों की महिलाओं को प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता सीमित है तथा गर्भनिरोधक और प्रजनन देखभाल तक उनकी पहुंच नियंत्रित है।
- मुस्लिम समुदाय की प्रजनन क्षमता के बारे में बयानबाजी सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं के बच्चे पैदा करने या न करने के अधिकार को प्रभावित करती है।
- इससे न केवल मुस्लिम महिलाओं के जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन होता है, बल्कि उनकी व्यक्तिपरकता भी प्रभावित होती है।
- इसलिए, जनसंख्या वृद्धि और प्रजनन क्षमता से संबंधित चर्चा का ध्यान यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों, व्यक्तिगत पसंद पर केन्द्रित होना चाहिए तथा राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रचार के लिए सह-चुनाव के प्रयासों का विरोध करना चाहिए।

फैक्ट फटाफट

1. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) शिपिंग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए की गई थी।
- इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है और इसका मुख्य कार्य अंतर्देशीय जलमार्गों में आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, नई परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का सर्वेक्षण करना और प्रशासन और विनियमन करना है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।

2. SBM-U 2.0

- इसका उद्देश्य भारतीय शहरों को कचरा मुक्त और सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को खुले में शौच से मुक्त बनाना है।
- इसमें ठोस अपशिष्ट के स्रोत पृथक्करण, 3R (कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण करना) के सिद्धांतों का उपयोग, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुराने डंप स्थलों के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इस योजना का परिव्यय 1.41 लाख करोड़ रुपये है।
- यह एक चक्राकार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन पर केंद्रित है जो ठोस और तरल अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में मानता है।
- इसका लक्ष्य लगभग 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में 100% नल जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज की व्यवस्था करना भी है।

3. भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (FIEO)

- भारतीय निर्यात संगठन महासंघ वैश्विक बाजार में भारतीय उद्यमियों की उद्यमशीलता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी।
- यह भारत में निर्यात संवर्धन परिषदों, सामुदायिक बोर्डों और विकास प्राधिकरणों का एक शीर्ष निकाय है।
- यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय और केन्द्र व राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, बंदरगाहों, रेलवे तथा निर्यात व्यापार सुविधा में लगे सभी लोगों के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है।
- यह देश के प्रत्येक वस्तु एवं सेवा क्षेत्र के 100000 से अधिक निर्यातकों के हितों की सेवा करता है।

4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)

- नवंबर 1945 में तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने और समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सलाहकार संस्था के रूप में स्थापित किया गया था।
- AICTE ने वर्ष 1987 में AICTE अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त किया।
- शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत AICTE भारत में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और विकास प्रदान करता है।
- यह भारतीय संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

5. केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS)

- यह आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- यह भारत में आयुर्वेदिक विज्ञान में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान करने, समन्वय करने, तैयार करने, विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय है।
- उद्देश्य: प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करके आयुर्वेदिक सिद्धांतों, औषधि उपचारों में वैज्ञानिक प्रमाण विकसित करना तथा निदान, निवारक, प्रोत्साहक और उपचार विधियों से संबंधित वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाना।
- गुणवत्तापूर्ण प्राकृतिक संसाधनों की निरंतर उपलब्धता के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना, उन्हें उत्पादों और प्रक्रियाओं में बदलना तथा संबंधित संगठनों के साथ तालमेल बिठाकर इन नवाचारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में शामिल करना

GEO IAS It's about quality
+91-9477560001, +91-9477560002, +91-9477560005
info@geoias.com
www.geoias.com
BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | Head office: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

प्रीलिम्स ट्रैक

Q1. भारत में आपराधिक कानूनों में हाल के सुधारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नये कानूनों का उद्देश्य न्यायिक निगरानी के बिना संदिग्धों की हिरासत और पूछताछ में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक विवेकाधिकार प्रदान करना है।
2. इनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
3. यह 1 जून 2024 से लागू होगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q2. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. इसमें भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए इन-सीटू झुग्गी पुनर्विकास का एक घटक शामिल है।
2. PMAY (शहरी) केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए उपलब्ध है
3. इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q3. अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इस योजना का उद्देश्य भारत के प्रमुख राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईंधन स्टेशन स्थापित करना है।
2. इस योजना के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा, जैसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।
3. यह योजना वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. सभी तीनों
D. कोई नहीं

Q4. भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CDS तीनों सेनाओं के सभी मामलों में प्रधानमंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
2. CDS रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का प्रमुख होता है।
3. CDS को तीनों सेवाओं: भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना की कमान संभालने का अधिकार है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q5. आर्टेमिस मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आर्टेमिस कार्यक्रम का नेतृत्व नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के सहयोग से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा किया जाता है।
2. आर्टेमिस मिशन का एक प्राथमिक लक्ष्य 2020 के अंत तक मानव को चंद्रमा पर वापस भेजना तथा वहां स्थायी उपस्थिति स्थापित करना था।
3. आर्टेमिस मिशन की योजना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने की है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q6. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. UAPA केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है, जबकि NSA व्यक्तियों को निवारक हिरासत में लेने की अनुमति देता है।
2. UAPA और NSA दोनों में किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 180 दिनों तक हिरासत में रखने का प्रावधान है।
3. NSA को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन UAPA केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q7. भारत में गन्ने की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. ब्राजील के बाद भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है।
2. चीनी उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है
3. उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q8. आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. यह एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसका मुख्यालय फ्रांस में है
2. अब 30 से अधिक देश इस गठबंधन का हिस्सा हैं और अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।
3. भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2
D. 1, 2, और 3

Q9. भारत में शारीरिक गतिविधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें

1. अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के मामले में भारत 195 देशों में 12वें स्थान पर है।
2. घरेलू काम-काज शारीरिक व्यायाम का एक अच्छा रूप है, यही कारण है कि महिलाएं विशेष रूप से फिट रहती हैं।
3. पिछले दो दशकों में भारतीय वयस्कों में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि की दर में तेजी से वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2, और 3

Q10. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS), मुंबई, सर्वेक्षण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है।
2. NFHS-5 के निष्कर्षों के अनुसार, भारत में पहली बार 2019-21 के बीच प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 वयस्क महिलाएं थीं।

दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1, न ही 2

प्रीलिम्स ट्रैक उत्तर

उत्तर : 1 विकल्प B सही है

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है** । नए कानूनों का उद्देश्य कानून प्रवर्तन की शक्तियों को व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित करना है और न्यायिक निगरानी के बिना संदिग्धों की हिरासत और पूछताछ में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक विवेक प्रदान करने की कोशिश नहीं करना है। इसके बजाय, सुधार आपराधिक न्याय प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **कथन 2 सही है।** महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक साइबर अपराधों के लिए कड़े दंड की शुरूआत शामिल है, जिसमें पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी शामिल है, जो डिजिटल युग में अपराधों की विकसित प्रकृति को दर्शाता है।
- **कथन 3 गलत है।** IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम की जगह नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू होंगे

उत्तर : 2 विकल्प A सही है

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) एक ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो देश भर में निम्न और मध्यम आय वाले निवासियों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है।
- इसमें क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, इन-सीटू स्लम पुनर्विकास, साझेदारी में किफायती आवास और लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण शामिल हैं। **कथन 1 सही है।**
- PMAY-शहरी के लाभार्थियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) शामिल हैं। **कथन 2 गलत है।**
- PMAY (शहरी), जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, को दिसंबर 2024 तक विस्तार दिया गया है। **कथन 3 गलत है।**

उत्तर : 3 विकल्प A सही है

व्याख्या

- अमृत भारत स्टेशन योजना विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईंधन स्टेशन स्थापित करने पर केंद्रित नहीं है।
- इसके बजाय, इसका मुख्य उद्देश्य संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) जैसे स्वच्छ और हरित ईंधन उपलब्ध कराने के लिए खुदरा दुकानें स्थापित करना है। **इसलिए, कथन 1 गलत है**
- अमृत भारत स्टेशन योजना का जोर संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) सहित स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर है।
- इन ईंधनों को पारंपरिक ईंधनों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प माना जाता है। **इसलिए, कथन 2 सही है**
- अमृत भारत स्टेशन योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल नहीं है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दायरे में आता है। **इसलिए, कथन 3 गलत है**

उत्तर : 4 विकल्प A सही है

व्याख्या :

- **कथन 1 सही है।** CDS सभी त्रि-सेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- **कथन 2 सही है।** CDS रक्षा मंत्रालय में नव निर्मित सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का प्रमुख है।
- **कथन 3 गलत है।** CDS के पास तीनों सेवाओं की कमान संभालने का अधिकार नहीं है। CDS तीनों सेवाओं के बीच एकीकरण और समन्वय के लिए कार्य करता है, लेकिन प्रत्येक सेवा (सेना, नौसेना और वायु सेना) का नेतृत्व उसके संबंधित प्रमुख द्वारा किया जाता है।

उत्तर : 5 विकल्प B सही है

व्याख्या:

- **कथन 1 गलत है।** आर्टेमिस कार्यक्रम का नेतृत्व नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा किया जाता है, जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है, लेकिन इसका नेतृत्व ESA द्वारा नहीं किया जाता है।
- **कथन 2 सही है।** आर्टेमिस मिशन का एक प्राथमिक लक्ष्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस लाना और 2020 के अंत तक एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना था।
- **कथन 3 सही है।** आर्टेमिस मिशन की योजना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और अगले पुरुष को उतारने की है।

उत्तर : 6 विकल्प A सही है

व्याख्या:

- **कथन 1 सही है** । UAPA केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की अनुमति देता है। NSA व्यक्तियों को भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोकने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए निवारक निरोध की अनुमति देता है।
- **कथन 2 गलत है।** UAPA के तहत, किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के अधिकतम 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है, लेकिन NSA बिना किसी मुकदमे के 12 महीने तक निवारक हिरासत की अनुमति देता है, जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
- **कथन 3 गलत है** । केंद्र और राज्य दोनों सरकारें NSA लागू कर सकती हैं। UAPA भी मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया जाता है, लेकिन इसे राज्य सरकारों द्वारा भी लागू किया जा सकता है।

उत्तर : 7 विकल्प B सही है

व्याख्या:

- ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। **कथन 1 ग़लत है।**
- कपास के बाद, चीनी उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृषि-आधारित उद्योग है। **कथन 2 गलत है।**
- उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जो देश के समग्र उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 8 विकल्प B सही है

व्याख्या:

- आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), 2019 में भारत की पहल पर स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। **कथन 3 गलत है।**
  - इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संधारणीय बनाना है।
- भारत में मुख्यालय वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, CDRI को इन बदलावों को लागू करने के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए। **कथन 1 गलत है।**
- 30 से अधिक देश अब इस गठबंधन का हिस्सा हैं और अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए CDRI के साथ काम कर रहे हैं। **कथन 2 सही है।**

उत्तर : 9 विकल्प C सही है

व्याख्या:

- अनुमान बताते हैं कि 195 देशों में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के मामले में भारत 12वें स्थान पर है। **कथन 1 सही है।**
- भारत में कई अध्ययनों से पता चला है कि जनसंख्या स्तर पर शारीरिक गतिविधि का स्तर कम है, खासकर महिलाओं में, जो गलत तरीके से मानती हैं कि घरेलू काम शारीरिक व्यायाम का एक अच्छा रूप है। **कथन 2 गलत है।**
- सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारतीय वयस्कों में अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि का प्रचलन 2000 में 22.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022 में 49.4 प्रतिशत हो गया है। **कथन 3 सही है।**

उत्तर : 10 विकल्प C सही है

व्याख्या

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS):

- NFHS एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला, बहु-चरणीय सर्वेक्षण है जो पूरे भारत में घरों के प्रतिनिधि नमूने पर किया जाता है।

आयोजित:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सर्वेक्षण के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) मुंबई को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। **इसलिए कथन 1 सही है।**
- सर्वेक्षण कार्यान्वयन के लिए IIPS कई क्षेत्रीय संगठनों (FO) के साथ सहयोग करता है।

NFHS-5 के मुख्य निष्कर्ष

- जन्म के समय लिंग अनुपात: भारत में पहली बार, 2019-21 के बीच, प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,020 वयस्क महिलाएँ थीं। **इसलिए कथन 2 सही है।**
- हालाँकि, डेटा इस तथ्य को कम नहीं करेगा कि भारत में अभी भी जन्म के समय लिंग अनुपात (SRB) प्राकृतिक SRB (जो कि प्रति 1000 लड़कों पर 952 लड़कियाँ है) की तुलना में लड़कों की ओर अधिक झुका हुआ है।
- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र निम्न SRB वाले प्रमुख राज्य हैं।

GEO IAS

It's about quality

ABOUT US

GEO IAS is the best institute for civil services in India for providing top quality teaching and materials, offering you most optimum path for your success in Civil Services exam. Our aim is to provide quality training with an affordable fee structure. Our uniquely designed course make us the best institute for UPSC to crack the exam in one go. We have a dedicated team of experienced and young teachers and counsellors who make sure that every student who joins the institute, must get customized way of preparation which matches with student's learning style.
The only institute of UPSC in India which has 3 AI enabled Mobile apps. We believe in Smart way of teaching and learning. The classes are available in offline as well as in online mode. We take the help of animation so that you may visualize the lectures. Unlimited tests for prelims and mains with solution in both form (Hard copy and soft copy). We have the set of 15 lac mcqs on each topic. We provide daily news analysis, Highlighted news paper and links of important Sansad TV shows. The institute has best success rate with more than 230 students have cleared the exam. HIGHEST RATED INSTITUTE as per GOOGLE, SULEKHA and JUST DIAL and the magazine on civil services

+91-9477560001 /002/005

BRANCH: Delhi Kolkata, Raipur, Patna | HEAD OFFICE: 641, Ramlal Kapoor Marg, Mukherjee Nagar, Delhi, 110009

info@geoias.com

www.geoias.com